लच्छी-धागे संबंधी बाध्यता से छूट

134. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1986 के तहत मई, 1990 में जारी की गई अधिसूचना के अन्तर्गत प्रकाशित लच्छी धागे संबंधी बाध्यता से उस राज्य की सहकारी कताई मिलों को छूट दिये जाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन बाध्यताओं को पूरा न कर पाने के संबंध में किन-किन कठिनाईयों का वर्णन किया गया है; और

(ग) इस मामले में यदि कोई निर्णय किया गया है, तो वह क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) महाराष्ट्र की सहकारी कताई मिल को छूट के लिये इसलिये अनुरोध किया गया क्योंकि हैंक यार्न बहुमात्रा में उपलब्ध है । सहकारी कताई मिलों के पास हैंक यार्न का काफी स्टाक एकत्रित हो गया है ।

(ग) चूंकि हैंक यार्न बाध्यता योजना इस आश्रय के साथ लागू की गई है कि समूचे देश के हथकरघा बुनकरों को निरन्तर आधार पर पर्याप्त मात्रा में हैंक यार्न उपलब्ध होता रहे इसलिये महाराष्ट्र की सहकारी कताई मिलों को हैंक यार्न बाध्यता से छूट देना व्यवहार्य नहीं है ।

Outstanding dues of Cooperative Cotton Growers' Marketing Federation with NTC .....

135. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that huge outstanding amount have fallen due from the National Textiles Corporation to different State Cooperative Cotton Growers' Marketing Federations towards purchase of cotton from time to time, if so, the total accumulaion of such dues as on December 31, 1994;

(b) the amount of outstanding dues to CCG Marketing Federation of Maharashtra and Gujarat; and

(c) what steps have been taken by Government and the NTC to clear the dues?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKATSWAMY): (a) to (c) Cotton is purchased by the National Textile Corporation on credit terms. Hence, there are bound to be certain outstanding dues for payment at any given point of time. The outstanding dues payable to different State Cooperative Cotton Federations as on 31-12-94 are Rs. 106.57 crores. Out of this, the amount due to the Maharashtra Federation and Gujarat Federation are Rs. 78.22 crores and Rs. 11.81 crores, respectively. Such outstanding dues are cleared from time to time, upon generation of resources and receipt of funds for liquidity and towards reimbursement of cash losses.

Requirement and availability of cloth

136. SHRI GOPAL SINH G. SOLANKI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the per capita requirement of cloth in metres by the end of Eighth Five Year Plan and the per capita availability of cloth in metres at present, State-wise; and

(b) the details of the action plan prepared by the Government to meet this requirement?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKATSWAMY): (a) The per capita requirement of cloth by the end of the Eighth Five

Year Plan has been estimated at around 33.58 sq. metres. The per capita availability of cloth during 1993-94 was estimated at 25.81 metres. However, statistics pertaining to the productaion and consumption of cloth is mainained on All India basis and not State-wise.

(b) Government has taken following steps to meet the requirement of cloth:—

(i) Removal of restriction on creation and expansion of capacity subject only to locational guidelines.

(ii) Permitting import of textile machinery under OGL and reduction in duty on such manhinery imports and

(iii) Measures to ensure availability of raw material to he industry through policy intervention whenever necessary.

वस्त्र अनुसंधान कोष

137. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण करने तथा उनकी वस्त्र संबंधी मदों में गुणात्मक सुधार लाने के लिये एक वस्त्र अनुसंधान कोष बनाने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कोष को कब तक बनाये जाने की संभावना है ; और

(घ) वस्त्र अनुसंधान संगठनों द्वारा वस्त्र संबंधी मदों तथा सूती धागे को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) वस्त्र अनुसंधान निधि की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) वस्त्र अनुसंधान संघों ने वस्त्र मशीनों के साथ-साथ फाइबर से लेकर फैब्रिक बनने तक वस्त्र मदों की गुणवत्ता में सुधार लाने के मुख्य उद्देश्य से अनुसंधान कार्य किया है ।

Textile Agreement with USA

138. SHRI ANANTRAM JAISWAL:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have recently signed any textile agreement with the USA; and

(b) if so, what are the details thereof and the future of the Indian fabrics stating the advantages expected by Government from the pact particularly in relation to the Mill make goods?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) Yes, Sir, Government have signed a textile agreement with the United States on 31st December 1994. The salient features of the Agreement are as follows:

(i) The current specific limit on Cat 369-O, comprising other cotton made-ups, has been removed.

(ii) The base levels for the categories 218 (Yarn Dyed Fabrics); 219 (Duck Fabrics); 313 (Cotton Sheeting); 342|642 (Cotton & MMF Skirts) 347|348 (Trousers|Slacks &